

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज से प्रकाशित

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज

शुक्रवार 20 अगस्त 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

क्रियायोग संदेश

स्थायी सुख, शान्ति व विभव्य वातावरण के लिए "क्रियायोग अभ्यास करें" सत्य की अनुभूति में सभी प्रकार के क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अव्याधिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि क्रियायोग के द्वारा हम सत्य से जुड़ जाते हैं। ज्ञान, शक्ति, शान्ति, आनन्द, नाम-यश, धन आदि के लिए मनुष्य को दृढ़-दर्भ भटकना पड़ता है, और प्राप्त न होने पर मनुष्य में हिंसक प्रवृत्ति प्रकट होती है। क्रियायोग में भवित दृढ़ होने पर ज्ञान, शक्ति, शान्ति, आनन्द, धन आदि सब कुछ स्वयं मनुष्य के पास आ जाते हैं।

क्रियायोग प्राचीनतम् एवं नित्य नवीन पूर्ण विज्ञान है। इश्वरीय नियमों के अनुसार कलिकाल में क्रियायोग का ज्ञान विलुप्त हो गया। आरोही द्वापर युग के आते ही मुख्यज्य अमर युरु भाष्यतार वावा जी द्वारा क्रियायोग को पुनर्जीवित कर पुनः परिव्यक्त किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी में भाष्यतार वावाजी ने क्रियायोग को महाशय के माध्यम से मानवकालितों को दिया। क्रियायोग ही सनातन धर्म में खणित यज्ञ है। क्रियायोग ही वेदधारा है। क्रियायोग अभ्यास से मनुष्य को अपने वार्तायिक स्वरूप "अहंवाहार्म" की अनुभूति एक ही जन्म में सम्भव है।

खामी श्री योगी सत्यम्
क्रियायोग अप्रम एवं अनुसंधान संस्थान
प्रयागराज

10 मिनट का अध्यास 20 वर्ष का विकास

यूपी चुनावः अमित शाह के घर पर हुई अहम बैठक

जेपी नहु और सीएम योगी के साथ साढ़े तीन घंटे तक मंथन



चर्चा की गई। गौरतलब है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई चर्चा हुई है। इसको लेकर एक चुनावी बैठक गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। इसको बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे थे। उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़ा, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बसल भी शामिल रहे। सीवी का दावा है कि करीब साड़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में हिस्सा लेने की पार्टी ने भी योगी में चुनाव लड़ने का भन बनाया है।

अमित शाह के घर इस बैठक में क्या चर्चा हुई? इस बारे में अपनाराजिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। लेकिन सीवी का दावा है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी राजनीति की पार्टी ने भी योगी में चुनाव लड़ने का भन बनाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद

तालिबान संकट के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, भारत के लिए बढ़ गई चुनौतियां



नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा रक्षयोग की आशयकता पर जोर देते हुए गुरुवार को कहा कि दुनिया में बदलते भूराजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं और जटिल हो रही हैं। इश्वरीक भूराजनीतिक हालात में लगातार आते रहते हैं। वह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप वैलेंज 5.0' के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। रक्षामंत्री ने कहा कि सुरक्षा चुनौतियों में तीनों बोर्डों में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं।

तालिबान या अफगान संकट का जिक्र किए बिना रक्षा मंत्री ने कहा, 'आज पूरी दुनिया में सुरक्षा के हालात तीजे से बदल रहे हैं। इस वजह से, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं और जटिल हो रही हैं। इश्वरीक भूराजनीतिक हालात में लगातार आते रहते हैं। वह 'डिफेंस इंडिया स्टार्टअप वैलेंज 5.0' के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। रक्षामंत्री ने कहा कि सुरक्षा चुनौतियों में तीनों बोर्डों में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं।

सदर, मोहाल, गोपीगंज, भदोही-221301

GSTIN : 09AAFTM3349D1ZK

PAN-AAFTM3349D Reg. No.: 1/2014

मिस्किन सेवा संस्थान ट्रस्ट

Misqueen Sewa Sansthan Trust (इण्डियन द्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंचीकृत)
श्रमिकों, मजलूमों, गरीबों अनाथों के सेवा में तत्पर
फाउण्ड प्रबन्धक: अहं अहम दिदीकी उर्फ
शहजादे पत्रकार/ग्राम प्रधान अल्वा कोरांव, प्रयागराज
कार्यालय: माजा गाली रोड, कोरांव-प्रयागराज, निवास ग्राम-अल्हा, देवघाट, कोरांव-प्रयागराज 212306
Mob.: 9450613192
E-mail: miskeenss2014@gmail.com, sahjadekoraon@gmail.com

पाण्डेय इंटरप्राइज़
SANTOOR
The secret of younger looking skin
प्रो० नितेन्द्र पाण्डेय
मो. 99364645661
सदर, मोहाल, गोपीगंज, भदोही-221301

पाण्डेय इंटरप्राइज़
INDIAN GRAVY
Suhana
TASTEMAKERS OF INDIA SINCE 1962
मटर पनीर मिक्स
MUTTER PANEER MIX
A true mix for North Indian delicacy with paneer and green peas.
प्रो० नितेन्द्र पाण्डेय
मो. 99364645661
सदर, मोहाल, गोपीगंज, भदोही-221301

समीर जनरल स्टोर
निःशुल्क प्रती होम डिलेवरी
प्रो० हरि मंगल दिंदं
मो. 7905259043
पता— बधवा ताहिरपुर, निवेणीपुरम्, झूंसी, प्रयागराज

यूएनएस में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लताड़ा, बताया कोरोना और आतंकवाद में क्या है कॉमन



नई दिल्ली (एजेंसी)। हमें यह याद रखना होगा कि आतंकवाद उसी तरह से घाटक है, जिस तरह से कोरोना। हममें से एक भी इससे सुरक्षित नहीं रहता। यह बात भारतीय विदेश मंत्री एवं यजयशंकर ने लिए खेतरों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की उच्च स्तरीय बैठक के संबोधित कर रखे थे। इसको लेकर एक राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खेतरों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की उच्च स्तरीय बैठक की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी राजनीति की पार्टी ने लोक चर्चा हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद

सीधे डीएसपी बनेंगे इंटरनेशनल खिलाड़ी : सीएम

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधे राज्यपाल अधिकारी पर की नकरी मिलेंगी, वह सीधे पुलिस में डीएसपी बनेंगे। सीएम योगी ने यह बात अलंकित तौर पर कहा है कि दुनिया में बदलते भूराजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं और जटिल हो रही हैं। इश्वरीक भूराजनीतिक हालात में लगातार आते रहते हैं। वह 'डिफेंस इंडिया स्टार्टअप वैलेंज 5.0' के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। रक्षामंत्री ने कहा कि सुरक्षा चुनौतियों में तीनों बोर्डों में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं।

सकता। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से लड़ने के लिए इसका सामर्थ्य नहीं दर्शाता। आतंकवाद के लिए विदेश मंत्री ने योगी की निर्देश को अनिवार्य ठोकरा दिया। इसको लेकर एक अलंकित ओलंपिक खिलाड़ियों को समानित करें दूर

सीधे योगी ने की बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान सीधे योगी ने दो खेलों को गोंदे ने की बड़ी घोषणाएं की। खेल जात में पश्चिमी यूरोपी को सौंगत देते हुए योगी ने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स यूनिसिटी में जरूर ध्यान देना नाम होगा। यूपी में खेलों को बढ़ाव देने के लिए सीधे योगी ने क्रीड़ाकारी, उत्तरी योगीय और सहायक विद्युतिकारों के बीच योगाएं और धनर्षी करते हुए सीधे योगी ने की अलंकित खिलाड़ियों पर धनर्षी करते हुए सीधे योगी ने की बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान सीधे योगी ने दो खेलों को गोंदे ने की बड़ी घोषणाएं की। खेल जात में पश्चिमी यूरोपी को सौंगत देते हुए योगी ने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स यूनिसिटी में जरूर ध्यान देना नाम होगा। यूपी में खेलों को बढ़ाव देने के लिए सीधे योगी ने क्रीड़ाकारी, उत्तरी योगीय और सहायक विद्युतिकारों के बीच योगाएं की। अलंकित खिलाड़ियों पर धनर्षी करते हुए सीधे योगी ने की बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान सीधे योगी ने दो खेलों को गोंदे ने की बड़ी घोषणाएं की। खेल जात में पश्चिमी यूरोपी को सौंगत देते हुए योगी ने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स यूनिसिटी में जरूर ध्यान देना नाम होगा। यूपी में खेलों को बढ़ाव देने के लिए सीधे योगी ने क्रीड़ाकारी, उत्तरी योगीय और सहायक विद्युतिकारों के बीच योगाएं की। इस दौरान सीधे योगी ने दो खेलों को गोंदे ने की बड़ी घोषणाएं की। खेल जात में पश्चिमी यूरोपी को सौंगत देते हुए योगी ने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स यूनिसिटी में जरूर ध्यान देना नाम होगा। यूपी में खेलों को बढ़ाव देने के लिए सीधे योगी ने क्रीड़ाकारी, उत्तरी योगीय और सहायक विद्युतिकारों के बीच योगाएं की। अलंकित खिलाड़ियों पर धनर्षी करते हुए सीधे योगी ने की बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान सीधे योगी ने दो खेलों को गोंदे ने की बड़ी घोषणाएं की। खेल जात में पश्चिमी यूरोपी को सौंगत देते हुए योगी ने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स यूनिसिटी में जरूर ध्यान देना नाम होगा। यूपी में खेलों को बढ़ाव देने के लिए सीधे योगी ने क्रीड़ा

ग्रामीण अचंल

खबर संक्षेप

बदनीयति से घर में घुसे युवक को किया पुलिस के हवाले

प्रयागराज। बदनीयति से घर में घुसे युवक को पकड़ कर परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के ठारुरी का

पुरा (लवाना) गांव के हहने वाले

एक युवक ने नवाबगंज थाने में

ठारुरी देवक बताया कि मैंलगवार

को वह रिश्टेदारी में गए थे।

घर में उनकी पुरी अकेली थी। जो के

ही राकेश पुरा राम सुमंगलवार

की तरह छत के रखते से घर के

अंदर आ गया। पुरी का मुंह

दबाकर छेड़खानी की शेर

मध्यांते पर परिवार और गांव के

एक एकत्र हो गए। सुबह आरोपी

राकेश को नवाबगंज पुलिस के

हवाले कर दिया। जिसमें

नवाबगंज पुलिस ने पर्व घर में

पुरी को लेकर बताया कि

विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

मोहर्म : नहीं निकलेंगी इमामबाड़े पर ताजिया : एसडीएम

थाना कोरांव को ऐन पर्व पर पीस कमेटी की बैठक की आई सुधि
ताजियादारों ने देव मन से माना हुम, कहा पहले हिदायत दी गई होती तो न
बनाते लोग ताजिया, कहा सिर्फ मुस्लिमों के त्योहारों पर होती है पार्वदिया

अखंड भारत संदेश

कोरांव। प्रयागराज। थाना कोरांव में आरोजत एन मोहर्म त्योहार के बर के बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित सभी के विचारों वाले को दी गई तर उप जिस दिन मोहर्म का चांद निकला था उसी दिन से ताजिया भी न बनाने की हिदायत दी गई होती तो ताजिया निर्माण में धन न व्यय किया जाता। कुछ ने कहा कि हर जगह भीड़ भाड़ है हर जगह बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं कि निनु सरकार ने मुस्लिम धर्म के ही लोहारों पे पार्वदियां लगाती हैं ताजियादारों ने सरकार की मंशा के मुताबिक



पीस कमेटी थाना कोरांव की बैठक में भाग लेते एसडीएम वी आम जन

ताजिया न निकालने का फैसला जन व प्रतकार, ताजियादार ग्राम प्रवान मुस्लिम समाज के लोग पूरी हो जाए बैठक में कुछ आम

पीस कमेटी की बैठक में ताजियादारों ने गिनाई समस्याएं

कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाएं पर्व : अवधेश



शंकरगढ़ थाना परिसर में हुई पीस कमेटी की बैठक

शंकरगढ़। मोहर्म के पर्व को लेकर शंकरगढ़ थाने में पीस कमेटी की बैठक का आरोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रिकारी बारा अधेश कुमार शुक्ल ने सभी ताजियादारों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का आशयसंकेत दिया। सीओ ने कहा कि सभी ताजियादारों से बोली की पर्व को संपन्न कराए। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करें। क्षेत्रिकारी बारा अधेश कुमार विवाह दिवाली देवताओं की बात कही, इस पर एसडीएम कुमार विवाह दिवाली देवताओं की बात कही, लैकिन जुलूस नहीं निकाला जाया। नावद तहसीलदार विश्वेनीक प्रियांती ने कहा कि शारिरिक माहौल में मोहर्म का पर्व नहाए। बैठक में एसआई अवर्देश सिंह यादव, व्यापार मंडल अधेश मूलगुप्त, महामंत्री रामन केसरवानी, उपाध्यक्ष जय केसरवानी, अविनेश केसरवानी, अर्पणा केसरवानी, राजेश केसरवानी, सम्मान सुनीता, उमा वर्मा, जयेश अहमद, छन्द मिया, विराग अली, मोहम्मद यूनस, गोलू खान, मोहम्मद साहिल, रसीद, मुख्तार अहमद आदि।

अनुप्रूक बजट में राहत न दिए जाने पर शिक्षकों ने की सरकार की निन्दा



जितेंद्र कुमार ने बीड़ीओं की रक्षणा

का पद भर ग्रहण किया

अखंड भारत संदेश



अनुप्रूक बजट में राहत न मिलने पर सरकार की निन्दा करते शिक्षक गण

बाबू ने सरकार को आगाह किया कि आगामी विवाहसंप्ति चुनाव की परवाह न करते हुए सरकार ने शिक्षक विरोधी निर्णय लेकर कल्पित मानविकता परिवर्चय दिया। बैठक में शिक्षकों ने प्रेस्स अधिकारी श्री लाल विहारी का प्रतिनिधि एवं केवल वाक्यपात्र को सराहना करते हुए विवाह परिषद में संसदीय समिति का सदस्य चुने जाने की बाबूही नी गई।

बैठक में अभ्यर्यात्र सिंह, गुलाब सिंह, फूलचंद कर्नानी, नवीन शुक्ला, सीताशरण सिंह, बुधराम यादव, बालेंदु गौतम, अमरबहादुर, मानसिंह पटेल, जेपी यादव, अमरचंद गुला, अवधेश श्रीवास्तव, कमलचंद, प्रेमचंद यादव, अविनेश कुमार, विवाह परिषद एवं संसदीय समिति का सदस्य चुने जाने की बाबूही नी गई।

विरोधी यादव ने है सरकार के साथ

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई। सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई।

सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई।

सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई।

सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई।

सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई।

सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई।

सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र में भी शिक्षकों को सेवा

निवाहन सत्र में भाग लेने का दंभ भरने सबाली बाजपा

सरकार को दूषित कराता उत्तरांत राहत को

कुचुक ही नी गई।

सब के जिलाध्यक्ष ननकेश

की तथा शिक्षा जगत के प्रति कठोरतम

वर्तमान सत्र म

विचार

सम्पादकीय एनडीए में महिलाएं!

कोर्ट का ध्यान मुख्य तौर पर इस बड़े सवाल पर था कि आखिर आर्मी में महिलाओं के सवाल पर खुलापन क्यों नहीं दिख रहाघ क्यों हर बार कोर्ट को दखल देकर फैसला सुनाना पड़ता है और फिर भी बात उस खास मामले से जुड़े फैसले पर अमल तक ही सीमित रह जाती है उससे आगे नहीं बढ़ती सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि आर्मी में महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अंतरिम आदेश के जरिए कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आगामी 5 सितंबर को होने वाली एनडीए, नैशनल डिफेंस अकॉर्डमीट्ट प्रवेश परीक्षा में महिलाएं भी बैठ सकेंगी। हालांकि उनका नामांकन इस मामले में आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा लेकिन कोर्ट के इस फैसले की अहमियत महज एडमिशन प्रॉसेस तक सीमित नहीं है।

कोर्ट का ध्यान मुख्य तौर पर इस बड़े सवाल पर था कि आखिर आर्मी में महिलाओं के सवाल पर खुलापन क्यों नहीं दिख रहाघ क्यों हर बार कोर्ट को दखल देकर फैसला सुनाना पड़ता है और फिर भी बात उस खास मामले से जुड़े फैसले पर अमल तक ही सीमित रह जाती है एवं उससे आगे नहीं बढ़तीघ गौर करने की बात है कि अन्य तमाम क्षेत्रों में तो महिलाएं काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी हैं लेकिन सेना में उनकी गति काफ़ी धीमी रही। करीब 14 लाख सैनिकों वाली आर्मी में आज भी महिलाओं का प्रतिशत ००५६ ही है। इस मामले में पिछले साल फरवरी में आया सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला ऐतिहासिक माना जाता है जिसमें अदालत ने न केवल महिलाओं को कमांड पोसिंग के लायक बताया बल्कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि उन्हें परमानेंट कमिशन दिया जाए।

ध्यान रहे उस मामले में महिलाओं को परमानेट कमिशन न दिए जाने के पक्ष में यह दलील भी दी गई थी कि सेना में ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जिनके लिए महिलाओं से आदेश लेना सहज नहीं है। कोर्ट ने न केवल इस दलील को खारिज किया बल्कि इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत बताई। उसके बाद हालांकि इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं लेकिन एनडीटी परीक्षा में महिलाओं को बैठने से रोकना और उसे नीतिगत मामला बताना स्वीकार्य नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को बैठने देने से ज्यादा अहमियत इस सवाल को दी कि आखिर सेना में इस मानसिकता को बदलने के कारण प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे। कोर्ट ने फिलहाल खुद को अंतरिम आदेश तक सीमित रखते हुए कहा कि हर मामले में उसके आदेश का इंतजार करना सही नहीं है। सरकार और सेना खुद आवश्यक कदम उठाकर अपनी नीति दुरुस्त करे। हालांकि सेना में लिंग निरपेक्ष नीतियों का मामला उतना सरल नहीं है। महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट और ठहरने की अलग व्यवस्था के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास भी जरूरी हैं जो रातोरात नहीं हो सकता। लेकिन महिलाओं को हर फील्ड में समान अवसर देने के संवैधानिक तकाजे को पूरा करने की राह में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद की जाए कि अब इस मामले में सेना और सरकार प्रो. ऐकिटव रोल में नजर आएगी।

जल योजना से बड़ी लाभ

नरेन्द्र नाथ

2019 में चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और पेयजल आपूर्ति के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक की योजना का ऐलान करवे।

डा. सुधा कुमारी

बहुत प्राचीन समय से हमारा समाज स्वच्छता और पारंपरिक वातावरण का समर्थक और पोषक रहा है। तन की स्वच्छता और स्वास्थ्य को तन के परिष्कार एवं व्यायाम द्वारा ऐसा मन की स्वच्छता और स्वास्थ्य का योग-अभ्यास एवं अनश्वासन द्वारा वातावरण की स्वच्छता को हरियाली और नदी, नालों, नौलियों की सफाई द्वारा इस प्रकार एक परिष्कार समाज के निर्माण का संकल्प किया गया। हड्डिया संस्कृति भारतीय स्वच्छ नगर, सभ्यता की एक सुन्दर मिसाल थी। प्रकृति और मनुष्य दोनों साथ, साथ वातावरण की भी हो। हरियाली जीवन में वातावरण, और हर जगह हो। इसका एक कारण यह है कि व्यायाम योग-ध्यान एवं पूजादृष्ट बबुल के साफ वातावरण में संभव है। किन्तु औद्योगिक क्रिया-कलापए बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण क्रिया-कलापों के बढ़ने से वातावरण की स्वच्छता घटी है और जल, प्रदूषण एवं प्रदूषण और जमीन पर गन्दीगी बढ़ी है बढ़ती जनसंख्या का एक परिणाम है। अशिक्षा और निर्धनता जिसकी झुग्गी, झोंपड़ी और चौराहे, गलियों में गन्दीगी का अम्बार लगा दिया है हवा और जल के प्रदूषण के कारण भ्रीन हाउसपैक्स, उत्सर्जन बढ़ा और घ्कार्बन फूटप्रिंट अम्बर वातावरण के 60% तक हो गया है। संपूर्ण मनुष्य जाति का घ्कार्बन फूटप्रिंट 1961 से 11 गुना बढ़ गया है। इससे भविष्य ध्यान बार्मिंघम और झ्काइमेट देंजेस का खतरा बढ़ा है। इससे भविष्य में मानव प्रजाति के अस्तित्व को संकट हो सकता है। यह एक बड़ी

भारत का दुश्मन नहीं है तालिबान, मोदी सरकार को उनसे सीधी बात करनी चाहिए

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

रुस और अमेरिका ने चाहे अफगानिस्तान में अरबों खरबों रुपए बहा दिए लेकिन आप अफगान जनता में भारत की जो सराहना है वह इन देशों की नहीं है। भारत खुद मालदार देश नहीं है लेकिन अफगानिस्तान के नव. निर्माण में भारत ने तीन बिलियन डॉलर लगाए हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार गिर चुकी है लेकिन तालिबान की सरकार ने अभी तक औपचारिक सत्ता, ग्रहण नहीं किया है। किसी भी देश में जब भी तख्ता, पलट होता है तो नए शासक की घोषणा तुरंत होती है लेकिन ऐसा लगता है कि तालिबान अभी सलाह, मशवरा में मशगुल है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि अशरफ गनी की साढ़े तीन लाख की फौज बिना लड़े ही हथियार डाल देगी। तालिबान को क्या ए अमेरिकियों को भी इत्यन ही था कि अफगान. सेना इतनी जल्दी धराशायी हो जाएगी। अमेरिका का जासूसीकृतं दुनिया का सबसे बड़ा और सक्षम तंत्र है लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडन भी बिल्कुल गलत सिद्ध हो गए। और भारत का तो कहना ही क्या घ वह दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है। उसका प्रधानमंत्री कार्यालय उसका विदेश मंत्रालय और उसका गुप्तचर विभाग टापता रह गया। उसे पता ही नहीं चला कि काबुल सूखे पत्ते की तरह टूट कर तालिबान के हाथ में पिरने ही वाला है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते भारत चाहता तो काबुल में संयुक्त राष्ट्र की शांतिकूसेना भिजवा सकता था लेकिन यह मौका उसे खो दिया। यह मौका तो अभी भी है। पिछले हफ्ते ही मैंने लिखा था कि तालिबान मूलतः पश्तूनों का संगठन है। आगर उसने हेरात और मजारे, शरीफकू जैसे गैर. पश्तून इलाके इतनी आसानी से कब्जा लिये तो कंधारए काबुल और जलालाबादकू जैसे पश्तून इलाके तो अपने आप उसकी शरण में आ जाएंगे लेकिन भारत सरकार ने कोई चतुराई नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जब लाल किले से भाषण दे रहे थे उस समय तालिबान काबुल के राजमहल में घुस रहे थे लेकिन उनके भाषण में इसकी ज़रा भी कोई चिंता नहीं दिखी।

अफगानस्तान में जो भा उथल, पुथल हाता है उसका सबसे ज्यादा असर पहले पाकिस्तान और फिर भारत पर होता है लेकिन आप जरा देखें कि अफगान, संकट में सबसे सक्रिय भूमिका कौन से देश अदा कर रहे थे अमेरिका चीन ए रूस ए तुर्की ए करते रहे यूर्एशिया और ईरान आदि! अफगान मुजाहिदीन और तालिबान ने रूस और अमेरिका के हजारों

जगनों का मात के घाट उत्तर दिया और उनके अरबा खरबा डालरा पर पानी फेर दिया लेकिन इसके बावजूद वे उनके साथ पिछले दो साल से खुलकर बात कर रहे हैं लेकिन भारत आज क्या कर रहा है घ भारत ने अपना दूतावास खाली कर दिया है। अपने राजदूत और अन्य राजनयिकों की जान बचाकर उन्हें किसी तरह भारत ले आया गया है। अभी भी भारत के लगभग डेढ़ हजार नागरिक वहाँ फंसे हड्हे हैं। क्या वजह है कि अमेरिका रूस एवं चीन इरान और तुर्की जैसे देशों ने काबुल में भारत की तरह अपने दूतावास खाली नहीं किए हैं घ क्या वजह है कि रूस एवं



और ईरान ने घोषणा कर दी है कि वे तालिबान के साथ सहयोग करेंगे और क्या वजह है कि भारत की बोलती बंद है और भारत सरकार का प्रवक्ता सिर्फ प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के बारे में चिंतित दिखाई पड़ रहा है यह ठीक है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकाल लाने में भारत सरकार मुस्तैदी दिखा रही है लेकिन क्या वह इस अफगान संकट में भारतीय राष्ट्रहितों की रक्षा करने का पर्याप्त प्रयत्न कर सकी है। रूस और अमेरिका ने चाहे अफगानिस्तान में अरबों खरबों रुपए बहा दिए लेकिन आम अफगान जनता में भारत की जो सराहना है वह इन देशों की नहीं है। भारत खुद मालदार देश नहीं है लेकिन अफगानिस्तान के नव. निर्माण में भारत ने तीन बिलियन डॉलर लगाए हैं। उसके दर्जनों नागरिकों और राजनयिकों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। भारत ने 200 किमी० की जरंज. दिलाराम सड़क बनाकर अफगानिस्तान को फारस की खाड़ी तक जाने का वैकल्पिक मार्ग दिलवा दिया है। पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता को

ऐच्छक बना दिया है। यह ठीक है कि हामामद करज़ई और अशरफ गनी सरकारों के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ रहे लेकिन वे खुद तालिबान के साथ खुलकर बात करती रहीं तो भारत सरकार को किसने रोका था घ कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सरकार अमेरिका के भरोसे रह गई।

तालिबान को हम अचूत मानते रहे क्योंकि वे पाकिस्तान के हमज़ोली रहे हैं लेकिन हम क्यों भूलते हैं कि तालिबान भारत के दुश्मन नहीं हैं। दिसंबर 1999 में जब हमारे अपहृत जहाज को कंधार ले जाया गया तब उसे छुड़वाने में तालिबान के सर्वीच्य नेता मुला उमर ने ही हमारी मदद की थी। प्रधानमंत्री अटलजी के कहने पर पीर गैलानी से मैं लंदन में मिलाए वाशिंगटन स्थित ज़ालिबानी राजदूतष अब्दुल हकीम मुजाहिद और कंधार में मुला उमर से मैंने सीधा संपर्क किया और हमारा जहाज मुक्त हो गया। अब भी तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। उसने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में तीन बिलियन डॉलर का निर्माण कार्य करने के लिए वह भारत की सराहना करता है। इसके अलावा तालिबान ने अभी तक जो घोषणाएं की हैं उनसे ऐसा लगता है कि पिछले 25 साल में उन्होंने कई सबक सीखे हैं। वे पहले से अधिक परिपक्व और उदार हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या अभी तक करजई और अब्दुला जैसे नेताओं की जान को खतरा नहीं हो जाता था तालिबान ने अफगान महिलाओं से सरकार में हिस्सेदारी की अपील की है। उसने सर्वसमावेशी सरकार चलाने की घोषणा की है। अभी तक भयंकर खून खराबे की कोई गंभीर खबर नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तालिबान काबुल में अब कोई मिली जुली सरकार चलाने के लिए तैयार हो जाए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वह भी तालिबान की विजय से बाग बाग है लेकिन वह डरा हुआ भी है। तालिबान नेता मुला बिरादर पाकिस्तानी जेलों में आठ साल काट चुके हैं। तालिबान के भी कई खुदमुख्तार गुट हैं। उनमें से कुछ दूरें लाइन को अवैध मानते हैं और पठानों का राज पेशावर तक चाहते हैं। इस समय इस्लामाबाद में गैर तालिबान नेताओं का एक दल काबुल में संयुक्त सरकार बनाने की कवायद भी कर रहा है। यदि इस मौके पर अमेरिका और चीन जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं उनके विदेश मंत्री भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो भारत अपनी दुम दबाए क्यों बैठा हुआ है भारत चाहे तो तालिबान से सीधा संवाद करके उन्हें लोकतांत्रिक मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।

अफगानिस्तान आतंकिस्तान बन गया पर दुनिया खामोश क्यों है?

अनुराग मिश्रा

अफगानिस्तान में तात्त्विकों का हुँकूरत आ चुका हा। भारत के बनाए संसद भवन में जेनप्रतिनिधियों के बैठने वाली कुसिंचों पर हथियार लिए आतंकियों की तस्वीरें अफगानिस्तान के कल का खतरनाक पूर्वानुमान लगाने पर मजबूर कर रही हैं। पहले की तरह अमेरिका और उसके मित्र देश पल्ला झाड़कर पलायन कर चुके हैं। सौचरे समझने की क्षमता रखने वाला दुनिया का हर शख्स इस समय अफगानिस्तान के हालात पर चिंतित है। उसके मन में एक ही सवाल कौंध रहा है। ऐसा क्योंच क्या

इस राका नहा जा सकता थाघ क्या लाकतात्रक सरकार का आतका हुक्मूत के सामने धृते टेकने से बचाया जा सकता थाघ जवाब में उगली अमेरिका की तरफ ठंडी है। उसे जब सूट किया तो उसने अफगानिस्तान में आक्रमण कर सत्ता को कठपुतली की तरह नचाया और जब खर्च उद्देश्यों पर भारी पड़ने लगे और अपना काम निपट गया तो देश को मज्जधार में छोड़कर उसके जहाज उड़ चले। वैसेह अमेरिका अपनी सफाई में भ्रष्टाचार और अन्य कारणों को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार बता रहा है। खैर अगर अमेरिका नहीं तो और कौनघ कैसे एक पूरा देश अफगानिस्तान से झातकिस्तानष् की राह पर चला गयाघ ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तीन फ्रांस यूके होते हुए कनाडा तक का मैं पैदेख डालिए। फिर नजरें अमेरिका पर हो टिकेंगी। जी हां यहीं

जल योजना से बीजेपी का राजनीतिक कल्पाण होगा

੧੨੫ ਨਾਥ

प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में किसा बड़ा योजना का ऐलान नहीं किया। यह संकेत जरूर दिया कि वह 2024 टेंट आम चुनाव में भी 2019 के विजय फॉर्म्युले को जारी रखेंगे। यानी वह अपनी सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को अधिक र अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचा कर लोगों के बीच गोट मांगने जाएंगे। इ बार भी पिछले साल की भाँति ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ज संरक्षण और हर घर पेयजल आपूर्ति को अपना अहम अंजेंडा बताया। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि जो कल्याणकारी योजनाएं अभी चल रही हैं उन्हीं पर फोकस बना रहेगा। पिछले दिनों ही पीएम मोदी ने गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण क शुरूआत की थी। मोदी की मंशा है कि 2024 तक वह कम से कम 2 करोड़ लोगों को ऐसा घर दें जिसमें बिजली, पानी, शौचालय और गैरिल सिलंडर की पहुंच हो और परिवार के कम से कम एक सदस्य के पानौकरी हो। दरअसल एनडीए सरकार को 2019 में प्रधानमंत्री आवाय योजनाएं शौचालय और उज्ज्वला जैसी योजनाओं का बड़ा लाभ मिल और गरीबों के बड़े तबके का गोट मिला। अब वह 2024 में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संकट और कोविड ने इ बार इसे अमल में लाना मुश्किल बना दिया है। सरकार को पता है ति इन योजनाओं का सियासी लाभ तभी मिलता है जब आम जन तव इसका असर दिखे।

2019 में चुनाव जीत हो प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और पर्यावरण का आपूर्ति के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक की योजना का ऐलान करते हुए किया।

घरों में नल का कनेक्शन है। जाहिर है कि अगर इन बड़े राज्यों में मोदी सरकार इस योजना के क्रियान्वयन में सफल रहती है तो गरीबों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल होगी। 75 सालों में गरीब जिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहेंगे मोदी सरकार उन्हें मुहैया कराने के लिए जोर लगाती रही है और उसे सामान्य विकास कार्यों से अधिक प्राथमिकता देती रही है। बैंक अकाउंट खोलने जैसे काम भी इसी पहल का हिस्सा थे। मोदी ने इन्हीं नीतियों की मदद से गरीबों के रूप में एक बड़ा वोट बैंक बनाया एं जिसमें जातियों की भी दीवार टूटी है।

लेकिन तय समय पर हर घर जल के लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं है। कॉरिडिंट के चलते इस योजना में पहले ही देर हो चुकी है और देश में जल संकट को देखते हुए इसे पूरा करने की राह कठिन होगी। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अभी लगभग 25 फीसदी की दर से सभी घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंच रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 60 करोड़ से अधिक लोग भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं। अगले दस सालों में पानी की मांग दो गुना बढ़ने का अनुमान भी इसी रिपोर्ट में किया गया है और जबकि इसके लिए मौजूद स्रोत में 5 फीसदी की कमी आ जाएगी। पूरे देश में जल स्तर जिस तेजी से मीठे जा रहा है उसका कोई लेखा जोखा इस योजना में नहीं है। ऐसे में जानकारों के अनुसार नल लगाना तो आसान है लेकिन निर्बाध जल स्पूर्झ आसान नहीं होगी। इस पर सरकार की सोच है कि अगर योजना आंशिक रूप से भी सफल रही तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही नई योजना के रूप में सरकार के सामने सबसे महत्वाकांक्षी योजना भी सिर्फ यही है। उसे पता है कि पुरानी योजनाओं का लाभ एक चुनाव में मिल गया एं दूसरी बार भी मिलेगा इसमें संदेह है।

परिष्कृत और सुखी वातावरणः आज की आवश्यकता

चुनौती है। 1995 से ही इस चुनौती का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्षुगेमेट यैंज कॉन्फरेंस सभा प्रदूषण एवं कार्बन फुटप्रिंट कम करने का प्रयास किया है। प्रतिवर्ष यह कान्फरेंस आयोजित होता है। 1997 में क्योटोए जापान में कार्बन उत्सर्जन एमिसन दूँ करने के नियम तय किये गए। क्योटो प्रोटोकोल के मुताबिक जो देश निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उन्हें क्षार्बन क्रेडिट भिलेगा। इसके बाद से संयुक्त सहमति एवं प्रयास से सफाईए स्वच्छताए करवे का निस्तारण योजनाएँ और ग्रीन टेकनेलॉजी को अपनाना सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनाई गई है जिसमें सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी है। क्योटो प्रोटोकोल को सभी देशों ने स्वीकार किया है और उन्होंने 1990 के कार्बन स्तर को करीब 7% कम करने का लक्ष्य तय किया। कार्बन क्रेडिट के साथ ही कार्बन ट्रेडिंग की भी व्यवस्था बनाई गई है। एपिशन ट्रेडिंग या एप एन्ड ट्रेड एसरकार द्वारा निर्धारित बाजार की व्यवस्था है। प्रदूषण कम करने के बाद आर्थिक प्रोत्साहन की धारणा है। अंतर्राष्ट्रीय एपेडिंग सिस्टम में जिन देशों ने कार्बन क्रेडिट पाया है वे अन्य देशों से इसका विनिमय कर सकते हैं। क्षार्बन ऑफसेट रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट गाटर रेस्टोरेशन सर्टिफिकेट कुछ ऐसे ही प्रवर्लित नाम हैं। कार्बन क्रेडिट जहाँ एक सकारात्मक प्रभाव रखता है वहाँ क्षार्बन टैक्स एक नकारात्मक उपाय है। यूरोप में कई देशों ने यह टैक्स लगा रखा है जिसके द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कार्बन गैस उत्सर्जन करनेवालों पर यह टैक्स लगाया जाता है। इस प्रणाली को अर्थसांस्कृती क्षार्बन प्राइसिंग के नाम से भी जानते हैं और समर्थन करते हैं। भारत की वर्तमान स्थिति में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। जहरीली गैसों का उत्सर्जन तेज शार. शराबाए दीवारों और सार्वजनिक वाहनों में लिखावट और गंदगीए

पानी तथा जमीन पर कचरा और सड़कों पर गन्दगी और टहलते हुए जानवर जो काट भी सकते हैं। कचरे का डिब्बा होते हुए भी बाहर कचरा फेंकना इधर उधर थूकना और पान तंबाकू के दाग छोड़ना आम दिनरात्रि का अंग है। दफ्तरों में फालतू कागज इटूटे, फूटे फर्नीचरों का ढेर और गंदी दीवारें एक सामान्य दृश्य हैं। भारत में कचरे के अंबार और लोगों में गंदगी के प्रति उदासीन दृष्टिकोण को देखते हुए कचरा फैलानेवाले व्यक्तियों दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जुरुमाना या कार्बन टैक्स या अन्य कोई आर्थिक व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता है। सिर्फ नारेबाजी पोस्टरों और बड़े बड़े लोगों का झाड़ू सहित फोटो खिचवाने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। जब गंदगी फैलाने पर ही जुरुमाना लग जाएगा तो लोगों को अपना काम छोड़कर सड़क पर झाड़ू उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। आखिर झाड़ू लगाने के लिये इतने सफाई कमियों की भर्ती क्यों हुई है घंटे अपने कार्य में मुस्तैद क्यों नहीं हैं घंटे यदि उनकी संख्या कम हैं और लोगों की भर्ती क्यों नहीं की गई। अतः कचरा फैलाने वाले पर जुरुमाना लगाना और सफाई कमियों से कार्य अच्छी तरह करवाना आवश्यक है। उन्हें दस्ताने एटोपीए मास्क और एप्रन भी मिलना चाहिये ताकि उन्हें गंदगी और धूल से सुरक्षा मिले। गंदगी साफ करते हुए कहीं वे स्वयं बीमारी ग्रस्त न हो जायें। वृक्षारोपण बढ़ाने के साथ साथ भारत में कचरे पर सख्त जुरुमाना कार्बन टैक्स लगाना एक कचरा, निस्तारण तथा उनका परिष्कार करके प्रि. साइक्लप्स करना एक कम लागत से कॉपोरेट और सूखे शौचालय बनाना दीवारों और गहानों पर से गंदगी हटाना ए बैकार जानवरों को रास्ते से हटाना बहुत आवश्यक है। अच्छी बात है कि कुछ महानगरों में कचरे का परिष्कार और निस्तार तेज गति से हो रहा है। कलकत्ता ए मुंबई दिल्ली और

बैगलुरु में यह कार्य बढ़ा है। किन्तु पूरे देश में अभी काफी प्रयास करने कि एवं सख्ती की आवश्यकता है। ओसलो; नॉर्वे द्वा शहर के अधिकांश भाग स्वचालित कचरा निराकरण से जुड़े हैं जो ज़ैंडरग्राउंड इनसिनरेटर ख में कचरे को जला देता है। वहाँ स्वच्छता दिवसों का भी आयोजन होता है। सिंगापुर ने कड़े नियमों से स्वच्छता को बनाए रखा है। अल्टी-कनाडाद्वारा और कोपेनहेंगन डेनमार्कद्वारा में कचरे से कप्पोस्ट बनानाए थे। साइकलश करनाए गंदीपरकड़ा जुर्माना आदिवायकियोग है। एडिलेड़; ऑस्ट्रेलियाद्वारा में विशाल क्षेत्रों में हारियाली और पार्क की व्यवस्था है। जापान में लोग स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। वैडिंग मशीन का इस्तेमाल कर वहाँ खाना पीना करने के बाद डस्टबिन में कचरा फेकते हैं। जापान न केवल बुलेट ट्रेन के लिये विख्यात है बल्कि अति स्वच्छ वातावरण के लिये भी। अमेरिका में कचरे पर 100 डॉलर से लेकर 1000 डॉलर तक का जुर्माना है। इसके राज्यों में बोतल बिल्स नामक कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बोतल डब्बे वापस करने पर रिफंड मिलता है। इन खाली डब्बों का निस्तारण विक्रेता की जिम्मेदारी है। भारत में इन उपायों को अपनाना अमेरिका में कचरे पर 100 डॉलर से लेकर 1000 डॉलर तक का जुर्माना है। इसके राज्यों में बोतल बिल्स नामक कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बोतल डब्बे वापस करने पर रिफंड मिलता है। इन खाली डब्बों का निस्तारण विक्रेता की जिम्मेदारी है। भारत में इन उपायों को अपनाना है अमेरिका में कचरे पर 100 डॉलर से लेकर 1000 डॉलर तक का जुर्माना है। इसके राज्यों में बोतल बिल्स नामक कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बोतल डब्बे वापस करने पर रिफंड मिलता है। इन खाली डब्बों का निस्तारण विक्रेता की जिम्मेदारी है। भारत में इन उपायों को अपनाना है अमेरिका में कचरे पर 100 डॉलर से लेकर 1000 डॉलर तक का जुर्माना है।

